अर्थव्यवस्था भी झटकों से उबर रही

डब्ल्यूएचओ इसे टीकों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करेगा या नहीं इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है। बहरहाल, अपने देश में तो यह टीका न केवल बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है बल्कि अब तक के अनुभवों पर खरा भी उतरा है।

आरती सिंह।।

देश में 2 से 18 साल उम्र तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका इस्तेमाल करने को लेकर एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिश ऐसे समय आई है जब कोरोना संक्रमण निचले स्तर पर है, जनजीवन सामान्य होने की ओर है और अर्थव्यवस्था भी झटकों से उबर रही है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सच है कि टीकाकरण अभियान बीच–बीच में रेकॉर्ड बनाने के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप रफ्तार हासिल नहीं कर सका है (19.8 फीसदी आबादी ही टीके के दोनों डोज ले सकी है) और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी समाप्त नहीं की जा सकी है। हालांकि इस टीके को अभी डीसीजीआई (ड्रग्स कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया) की मंजूरी नहीं मिली है।

लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी (एसईसी) की सिफारिश के रूप में एक अहम पड़ाव पार कर लेने के बाद इस टीके से होने वाले नफा–नुकसानों की चर्चा होने लगी है। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसके तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल डेटा को लेकर सवाल बने हुए हैं। कोवैक्सीन को सुरक्षित वैक्सीन के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। डब्ल्यूएचओ इसे टीकों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करेगा या नहीं इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है। बहरहाल, अपने देश में तो यह टीका न केवल बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है बल्कि अब तक के अनुभवों पर खरा भी उतरा है।

फिर भी डब्ल्यूएचओ की मान्यता में देरी का असर इस रूप में जरूर देखने को मिल सकता है कि सरकार की मंजूरी मिल जाने और टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिए जाने के बाद भी इसे लेने में लोग शुरू में कुछ हिचक दिखाएं। मगर हर टीके को लेकर शुरू में ऐसी हिचक देखी जाती रही है जो समय के साथ दूर होती है। इससे पहले अगस्त में जायडस कैडिला के कोरोना टीके को भी आपात कालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, लेकिन वह 12 से 18 साल के बच्चों के लिए था।

पहली बार इस टीके के जरिए 2 साल की उम्र तक के बच्चों को कवर करने की सोची जा रही है। इससे न केवल तीसरी लहर में बच्चों के मुख्य निशाना होने संबंधी चिंता को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि स्कूलों की पढ़ाई को सामान्य बनाना भी आसान होगा। स्कूल खुलने के बावजूद ऑफलाइन पढ़ाई अभी कई तरह की बंदिशों के बीच ही चल रही है। हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी उपकरणों तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई से स्टूडेंट्स की समझ में होने वाले इजाफे को लेकर कई तरह के सवाल हैं। निश्चित रूप से टीके की सुरक्षा और उसकी कारगरता को लेकर सारे संदेह पहले दूर कर लिए जाएं, लेकिन उसके बाद बच्चों को टीकाकरण के दायरे में जल्द से जल्द लाना सबके हित में होगा।

ढिंढोरा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

काफी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुरदे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे पांच सौ सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में उक्त ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित कौर व्यक्ति मरने को तैयार हो? आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि वह सुख से खाता पीता, सोता नहीं था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेशानुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर बाकयदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया।

संपादकीय

नई–नई मांगें

शासक के सामने हमेशा ये दिक्कत रहती है कि अगर वह अपने एक फैसले के लिए माफी मांगता है तो उसके विरोधी कई दूसरे भी फैसलों की वापसी के लिए कुतर्क पेश करने लगते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद ऐसा होने लगा है। ऐसी मांगों का कोई अंत नहीं होता। सियासी मैदान में विरोधी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे करतब होते रहेंगे। पर लोकतंत्र में बहुमत के साथ ही लचीला रुख अपनाने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करना निहित है। यह मामूली बात नहीं है कि निरंकुश और अड़ियल समझी जाने वाली शख्सियत अपने मान और अपमान को किनारे रखकर उन कानूनों की वापसी के लिए देश से माफी मांग ले, जिसे वह अब भी खराब नहीं मानती। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र कुमार अलघ की कभी ना तो संघ परिवार से नजदीकी रही, ना कभी वे नरेंद्र मोदी के करीबी रहे। लेकिन कानून वापसी के अगले ही दिन लिखे अपने लेख में उन्होंने माना है कि इस कानून को अगर कड़ी–दर–कड़ी लागू किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा है कि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये कानून खराब नहीं थे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद मांग उठने लगी है कि प्रधानमंत्री इसी तरह नागरिकता संशोधन कानून को भी वापस लें। आने वाले पांच राज्यों के चुनाव इसका भी फैसला कर देंगे कि अपने देश में मतदाताओं को लचीलापन स्वीकार्य है या अड़ियलपन।

बीजेपी विरोधी एक मुखर दल की सरकार के एक मंत्री ने इन पंक्तियों के लेखक से दो दिन पहले एक बातचीत में कहा कि 'प्रधानमंत्री ने अपनी छवि के उलट जाकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है।

अपने–अपने नैरेटिव

उमेश चतुर्वेदी।।

राजनीति विज्ञान में किसी पश्चिमी विचारक का प्रधानमंत्री पद के लिए एक कथन खूब पढ़ाया जाता है। इसके जरिए बताने की कोशिश होती है कि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद की क्या अहमियत होती है। इस कथन के अनुसार, प्रधानमंत्री देश रूपी जहाज का मस्तूल होता है। पानी के जहाज में मस्तूल का वही काम होता है, जो कार–बस में स्टीयरिंग का। इस कथन के संदर्भ में देखें तो तीन कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत होना चाहिए। लेकिन पिछले साल नवंबर से आंदोलनरत तबके अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार ही नहीं। बल्कि, उनकी मांगों की फेहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है।

चूंकि वैचारिकी और राजनीति के लिहाज से मुफीद विचारों का ही समर्थन आज के दौर का चलन है, इस वजह से विरोधी खेमे और वैचारिकी वाले वे लोग भी प्रधानमंत्री के इस कदम का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी सोच बदलती नजर आ रही है। बीजेपी विरोधी एक मुखर दल की सरकार के एक मंत्री ने इन पंक्तियों के लेखक से दो दिन पहले एक बातचीत में कहा कि 'प्रधानमंत्री ने अपनी छवि के उलट जाकर बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। देश और लोकतंत्र के हित में इस लकीर का सम्मान किया जाना चाहिए।' यह बात और है कि इस सोच को वह अपनी ही पार्टी में जाहिर नहीं कर पा रहे।

सोशल मीडिया के दौर में सबके अपने–अपने नैरेटिव हैं और उसी के अनुरूप अपने–अपने चहेतों और विरोधियों की छवियां हैं। नैरेटिव के हिसाब से सबके अपने दुश्मन हैं और सब उन्हें अपनी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प है कि सारा कुछ देश और लोकतंत्र को बचाने के नाम पर हो रहा है। सच पूछें तो देश और लोकतंत्र की असल चिंता अगर कहीं है, तो वह 'ऑफ द रेकॉर्ड' वाले विचारों और ठेठ देसज सोच में ही बची रह गई है। जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया तो देसज सोच और 'ऑफ द रेकॉर्ड' वाली वैचारिकी को लगा कि अब प्रधानमंत्री की अपील के मुताबिक किसान अपने घरों और खेतों में लौट जाएंगे। लेकिन जिस तरह का रुख किसान आंदोलन ने दिखाया है, उससे उस आंदोलन का समर्थन कर रहा तबका भी मुतमईन नजर नहीं आ रहा है। उसे भी अब महसूस होने लगा है कि किसानों के नाम पर दरअसल राजनीति हो रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की छवि उनके विरोधियों की नजर में निरंकुश और अड़ियल शासक की रही है। हालांकि इस सोच को चुनौती नागरिकता संशोधन विरोधी आंदोलन के साथ ही किसान आंदोलन भी देता रहा है। दोनों आंदोलनों को पुलिस या सेना के दम पर दबाने की सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री चाहते तो यह नहीं हो सकता था। राजनीति विज्ञानी मानते ही हैं कि संसदीय लोकतंत्र में बहुमत दल का नेता बहुमत के चलते निरंकुश बन सकता है। लेकिन कम से कम नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलन को कुचलने की प्रत्यक्ष प्रशासनिक कोशिश नजर नहीं आई। कृषि कानूनों की वापसी कलिंग विजय के बाद विचलित अशोक की धम्म यात्रा जैसी है।

सूडोकु नवताल-5240

सरल

5		9		8	3	2		
	2		4					8
3	8		5	2	6	1		
	7						9	5
9		3	6		8	7		4
2	6						1	
		5	2	7	1		8	6
6					4		7	
		8	9	6		4		2

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5239 का हल

8	2	5	3	6	7	9	1	4
4	6	1	8	9	2	3	7	5
3	7	9	1	5	4	6	8	2
1	3	7	4	2	9	5	6	8
6	5	2	7	1	8	4	9	3
9	8	4	6	3	5	1	2	7
2	4	6	9	8	3	7	5	1
5	1	3	2	7	6	8	4	9
7	9	8	5	4	1	2	3	6

अपना ब्लॉग

जिंदगी की नई यात्रा शुरू हुई

मोहन। प्रतिपक्षी दल के एक नेता ऑफ द रेकॉर्ड कथन में प्रधानमंत्री की तुलना अशोक से करने लगे हैं। अशोक का राज्याभिषेक ईसा पूर्व 270 में हुआ। तब से लेकर ईसा पूर्व 261 तक उसने लगातार मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। तब तक अशोक बड़ा और प्रतापी रहा। लेकिन कलिंग विजय के बाद जब वह धम्म यानी बौद्ध धर्म की ओर झुका, तब उसकी जिंदगी की नई यात्रा शुरू हुई। इसके बाद ही वह महान माना गया। तलवार के बजाय करुणा के दम पर शुरू हुई विश्व विजय यात्रा ही अशोक को महान बनाती है। इन संदर्भों के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भी अशोक की कलिंग विजय से पहले तक की यात्रा जैसी ही रही है। नोटबंदी हो या कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 का खात्मा, राममंदिर का निर्माण हो या फिर तीन तलाक जैसी दारुण व्यवस्था का समापन– इन तमाम कदमों से प्रधानमंत्री मोदी का कड़क रुख ही जाहिर होता रहा है।